- 19th Year
- Issue: 298
- 10.03.2026 (TUESDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

सुनवाई होने तक आरोपमुक्त नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल एवं सिसोदिया, ट्रायल कोर्ट ने अहम तथ्यों को नजरअंदाज किया

नयी दिल्ली ०९/०३ (संवाददाता): दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की याचिका पर केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को नोटिस जारी किया। सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करने का निचली अदालत का आदेश अनुचित है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि उत्पाद शुल्क नीति का मामला सबसे बड़े घोटालों में से एक है और भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है।

मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य को बिना सुनवाई के ही बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने शराब नीति में हेरफेर के लिए साजिश और रिश्वतखोरी को दर्शाने वाले पुख़्ता सबूत जुटाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और गवाह सीबीआई के मामले का समर्थन करते हैं। सीबीआई ने कहा कि हमारे द्वारा जुटाए गए सबूतों को नजरअंदाज किया गया है और केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और गवाह सीबीआई के मामले का समर्थन करते हैं। पिछले हफ़्ते दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि शराब नीति की जांच के दौरान सीबीआई द्वारा जुटाए गए सबूत नीति को छिपाने, एकतरफापन या संवैधानिक अधिकार के बहिष्कार का प्रथम दृष्टया मामला उजागर करने में विफल रहे, और इस मामले में पूर्व उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह, केंद्रीय जांच ज़्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर शराब नीति मामले में आरोपी सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व मुख़्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता और 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। 598 पृष्ठों के अपने आदेश में न्यायालय ने कहा, वर्तमान में उपलज़्ध सामग्री से नीति को छिपाने, एकतरफा कार्रवाई करने या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने का प्रथम दृष्टया मामला सामने नहीं आता है। इसके विपरीत, रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रक्रिया परामर्श, संचार और प्रशासनिक सावधानी से संचालित थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिसोदिया ने रवि धवन समिति की उस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया था जिसमें उत्पाद शुल्क नीति में विसंगतियों का उल्लेख किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह नीति पिछली उत्पाद शुल्क नीति की चुनौतियों को दूर करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें वितरण मार्जिन में सुधार भी शामिल है, जो पिछली व्यवस्था के तहत एकाधिकार की प्रवृज़ियों और नियामक खामियों को दूर करने के प्रयासों को दर्शाता है।

विपक्ष पर भड़के नड्डा

नयी दिल्ली ०९/०३ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को पश्चिम एशिया संघर्ष पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन के दौरान विपक्ष द्वारा की गई नारेबाजी की निंदा करते हुए कहा कि विपक्ष को बहस करने में नहीं बल्कि केवल अराजकता फैलाने में दिलचस्पी है। विपक्ष पर अपने फायदे के लिए राजनीति करने का आरोप लगाते हुए नड्डा ने कहा कि वे इसमें कभी सफल नहीं होंगे। राज्यसभा में नड्डा ने कहा कि अत्यंत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का व्यवहार बेहद गैरजिज़्मेदाराना और निंदनीय है। उन्हें न तो देश में कोई रुचि है और न ही बहस में, बल्कि उन्हें केवल अराजकता फैलाने में रुचि है। नड्डा ने आगे कहा कि उन्हें विकसित भारत, देश की प्रगति में कोई रुचि नहीं है, उनकी रुचि केवल अपने फायदे की राजनीति में है, जिसमें वे कभी सफल नहीं होंगे। इन हमलों में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और सज़ारूढ़ दल के कई प्रमुख सदस्यों की मौत हो गई थी।

राहुल गांधी एक फेल एलओपी: संसद में पियुष गोयल का कांग्रेस पर हमला

नयी दिल्ली ०९/०३ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पहले से निर्धारित बहस के दौरान पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा की मांग करने के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। इससे पहले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों सदनों को सूचित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति के संबंध में सदनों को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने पुष्टि की कि सरकार ने क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के लिए औपचारिक सलाह जारी की है।

हालांकि, विपक्षी सांसदों ने मंत्री के बयान के बजाय चर्चा की मांग करते हुए नारे और तज़्तियां उठाईं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को विफल विपक्ष नेता बताते हुए, पीयूष गोयल ने भारत गठबंधन के भीतर दरार का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर सदन में अशांति फैलाने और समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अनुरोध पर नोटिस स्वीकार किया गया था। उनसे चर्चा के बाद यह तय किया गया कि इस पर आज चर्चा होगी। आज इस पर बहस होगी। इसी बीच वे एक और प्रस्ताव लेकर आ गए। उन्हें न तो संसदीय प्रक्रिया की समझ है और न ही संविधान का सज़्मान। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विपक्ष के नेता बनने के बाद से संसद चलाने की उनकी इच्छा मानो खत्म हो गई है। वे पहले से तय रणनीति के साथ आते हैं। तज़्तियां लेकर आते हैं। सदन में अशांति फैलाते हैं। बेबुनियाद मुद्दों पर संसद का समय बर्बाद करते हैं। उनके अपने ही गठबंधन के सदस्य इस बहस से भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है। राहुल गांधी विपक्ष के एक असफल नेता हैं। उन्हें न तो संविधान की समझ है और न ही संसदीय प्रक्रिया, कार्यप्रणाली या नियमावली में उनकी कोई रुचि है। उनके काम करने के तरीके से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस एक दिशाहीन, पूरी तरह से विफल विपक्षी दल है। मेरा मानना ??है कि उनके सहयोगी, डीएमके और टीएमसी, भी यह समझने लगे हैं, और इसीलिए उन्होंने आज की बहस में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इससे पहले आज, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के संसदीय बयान को लेकर केंद्र की आलोचना की और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए थरूर ने कहा कि बिना चर्चा के बयान पढ़ना सांसदों के लिए अन्यायपूर्ण है।

लोस अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, किरेन रिजिजू ने संभाला मोर्चा, कहा-मिलेगा करारा जवाब

नयी दिल्ली ०९/०३ (संवाददाता): केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे। विपक्ष ने ओम बिरला पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। 118 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर बोलने नहीं दिए जाने के बाद अध्यक्ष के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, रवि शंकर प्रसाद और भर्तृहरि महताब इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। सूत्रों के अनुसार, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के चिराग पासवान भी सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले दिन में, किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए चेतावनी दी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर उन्हें पछतावा होगा।

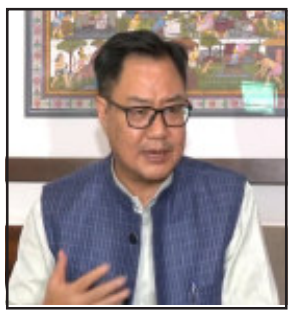

पत्रकारों को संबोधित करते हुए रिजिजू ने स्पीकर का बचाव करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव बिना किसी कारण के और केवल एक व्यक्ति की हठधर्मिता को संतुष्ट करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सदन में इसका करारा जवाब देने के लिए तैयार है और प्रस्ताव की हार की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग आज से शुरू होने वाला है। दुख की बात है कि इसकी शुरुआत लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव से हो रही है। हम इसका जवाब देंगे, लेकिन कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि संवैधानिक पदों और संवैधानिक गरिमा को कमजोर करने के लिए वे कितनी हद तक जा सकते हैं। वे अदालत की टिप्पणियों की आलोचना करते हैं। वे चुनाव आयोग की अवहेलना करते हैं।

भाजपा ने विदेश नीति गिरवी रख दी है-अखिलेश यादव

नयी दिल्ली ०९/०३ (संवाददाता): संसद सत्र से पहले, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की विदेश नीति को %गिरवी% बताते हुए उस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने बढ़ती महंगाई का हवाला देकर मध्य पूर्व में फंसे भारतीयों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया और कहा कि इंडिया ज़्लॉक की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने सोमवार को इंडिया ज़्लॉक के नेताओं की बैठक से पहले भाजपा की विदेश नीति के प्रबंधन की कड़ी आलोचना की। इंडिया ज़्लॉक के नेताओं की बैठक के एजेंडे पर चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में भारत की विदेश नीति गिरवी रखी गई है। बढ़ती महंगाई के प्रभाव को उजागर करते हुए उन्होंने दावा किया कि मध्य पूर्व में फंसे कई भारतीय नागरिक मौजूदा संकट के कारण त्योहार नहीं मना पा रहे हैं।याद ने पत्रकारों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के तहत हमारी विदेश नीति गिरवी रखी गई है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वहां फंसे हमारे कई भारतीय नागरिक कई त्योहार नहीं मना पा रहे हैं... आखिर भारतीय सरकार कर ज़्या रही है?

मुख्तार नक्वी ने ईरानी राजदू त से की मुलाकात, अयातुल्ला खामेनेई के निधन पर जताया गहरा दुख

नयी दिल्ली ०९/०३ (संवाददाता): भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुज़्तार अज़्बास नकवी सोमवार को नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। दूतावास में नकवी ने ईरानी राजदूत से मुलाकात की और दिवंगत नेता खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने ईरान के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट कीं।

मीडिया से बातचीत करते हुए नकवी ने कहा कि बुद्ध की धरती भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात को दोहराते हुए कहा कि किसी भी समस्या का हल केवल शांति के रास्ते से ही संभव है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज़्स पर अपनी भावनाएं साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वह खुद एक बड़ी समस्या है। मानवता की रक्षा के लिए शांति अनिवार्य है। उन्होंने प्रार्थना की कि इस संकट की घड़ी से शांति का मार्ग प्रशस्त हो।गौरतलब है कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु हो गई थी। इस हमले में उनके साथ कई अन्य ईरानी नेता और सैन्य अधिकारी भी मारे गए थे।

संसद का सामना नहीं कर पायेंगे पीएम मोदी, पश्चिम एसिया पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

नयी दिल्ली ०९/०३ (संवाददाता): लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि सरकार संसद में पश्चिम एशियाई संकट पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, ज़्योंकि इससे यह उजागर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और इज़राइल के दबाव में कैसे झुक गए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति जनता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है, ज़्योंकि वहां के संघर्ष से तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। रायबरेली सांसद ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से कितना नुकसान होगा? एक बड़े बदलाव की दिशा में संघर्ष चल रहा है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा।

आपने शेयर बाजार देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। देश को बड़ा झटका लगने वाला है। तो फिर इस पर चर्चा करने में उन्हें ज़्या समस्या है? हम इसके बाद अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ज़्या पश्चिम एशिया महत्वपूर्ण नहीं है? ज़्या ईंधन की कीमतें और आर्थिक तबाही चर्चा के महत्वपूर्ण विषय नहीं हैं? ये जनता के मुद्दे हैं।गांधी ने कहा कि अगर पश्चिम एशिया संकट पर दोनों सदनों में चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री संसद का सामना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इसे महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं... लेकिन वे चर्चा नहीं करना चाहते ज़्योंकि इससे अन्य बातें सामने आएंगी, प्रधानमंत्री की छवि खराब होगी। उनका पर्दाफाश हो जाएगा। यह बात सामने आ जाएगी कि वे कैसे समझौता कर रहे हैं और कैसे उन्हें ज़्लैकमेल किया जा रहा है। इसलिए वे चर्चा नहीं करना चाहते। आपने देखा कि प्रधानमंत्री संसद से कैसे भाग गए। मैं आपको बता रहा हूं, वे नहीं आ पाएंगे।पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। निचला सदन 10 मार्च को सुबह 11:00 बजे फिर से बैठेगा। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार को तीव्र टकराव के साथ हुई, ज़्योंकि भाजपा सांसदों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष पर पश्चिम एशिया संघर्ष पर विरोध प्रदर्शन करके कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। इससे पहले, इंडिया ज़्लॉक के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर पश्चिम एशिया विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

ब्लू स्पैरो मिसाइल इजराइल से हासिल करने की दिशा में भारत ने बढ़ाए कदम

नयी दिल्ली ०९/०३ (संवाददाता): जिस मिसाइल से ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की तेहरान में मौत हुई, उसी मिसाइल श्रेणी की उन्नत प्रणालियां भारत भी अपनी सैन्य क्षमता में शामिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 28 फरवरी 2026 को तेहरान में खामेनेई के कड़े सुरक्षा वाले परिसर पर किये गये सटीक हमले में ज़्लू स्पैरो नाम की वायु से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किये जाने की खबर सामने आयी है। इस घटना ने न केवल ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष को नया मोड़ दिया बल्कि इस बात पर भी ध्यान केंद्रित कर दिया है कि भारत पिछले कुछ वर्षों से इसी स्पैरो मिसाइल समूह से विकसित प्रणालियों को अपनी गहरी मारक क्षमता का हिस्सा बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह हमला तेहरान की पाश्चर स्ट्रीट पर स्थित खामेनेई के कड़े सुरक्षा वाले आवासीय परिसर पर किया गया। उस समय वहां ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक अधिकारी एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए मौजूद थे। इस हमले में लगभग तीस सटीक प्रहार किये गये जिनमें कई ज़्लू स्पैरो मिसाइलें शामिल थीं। हमले के बाद तेहरान के कई हिस्सों से धुएं के गुबार उठते हुए देखे गये और उसके बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने 86 वर्ष के खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी। बताया जाता है कि यह हमला एक लड़ाकू विमान से दागी गयी मिसाइल द्वारा किया गया जो अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचकर फिर अत्यधिक गति से नीचे आयी। ज़्लू स्पैरो लगभग 1240 मील तक मार करने में सक्षम मानी जाती है। इसकी उड़ान पद्धति अर्ध बैलिस्टिक होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल से कुछ समय के लिए बाहर चली जाती है और फिर तीव्र कोण से लक्ष्य पर गिरती है। इस विशेष उड़ान मार्ग के कारण सामान्य वायु रक्षा प्रणालियों के लिए इसे पकड़ना बेहद कठिन हो जाता है और लक्ष्य को लगभग बिना चेतावनी के भेदा जा सकता है।

ज़्लू स्पैरो मूल रूप से इजराइल के स्पैरो मिसाइल समूह का हिस्सा है। इस समूह में ज़्लैक स्पैरो और सिल्वर स्पैरो जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं। शुरुआत में इन्हें दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों की नकल करने के लिए विकसित किया गया था ताकि इजराइल अपनी वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण कर सके। लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव किये गये और इसे वास्तविक युद्ध अभियानों के लिए भी सक्षम बनाया गया। लगभग साढ़े छह मीटर लंबी और करीब दो टन वजनी यह मिसाइल आधुनिक लड़ाकू विमानों से छोड़ी जा सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार इस हमले के पीछे कई वर्षों की खुफिया तैयारी थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और साइबर खुफिया इकाई ने खामेनेई की सुरक्षा व्यवस्था और गतिविधियों पर लंबे समय तक निगरानी रखी। निगरानी में यातायात कैमरों और संचार नेटवर्क की जानकारी भी शामिल थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक खामेनेई अज़्सर अपने घर के नीचे बने गहरे बंकर में रात बिताते थे ताकि हवाई हमलों से सुरक्षित रह सकें। इसी कारण हमले की योजना सुबह के समय बनायी गयी जब वह अपने वरिष्ठ कमांडरों के साथ जमीन के ऊपर बैठक में मौजूद थे।

हमले से ठीक पहले साइबर इकाइयों ने आसपास के क्षेत्र में मोबाइल संचार को बाधित कर दिया ताकि किसी प्रकार की चेतावनी परिसर तक न पहुंच सके। इसके बाद सुबह करीब साढ़े सात बजे लड़ाकू विमान उड़ान भरकर निर्धारित स्थान तक पहुंचे और लगभग नौ बजकर चालीस मिनट पर मिसाइल प्रहार शुरू हुआ। बाद में पश्चिमी इराक में मिसाइल के अवशेष मिलने की खबर भी सामने आयी जिससे उसके संभावित उड़ान मार्ग का संकेत मिलता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत की सामरिक तैयारी से भी जुड़ा हुआ है। भारत पिछले कुछ वर्षों से इसी स्पैरो समूह से विकसित मिसाइल प्रणालियों को अपनी वायु सेना की गहरी मारक क्षमता का हिस्सा बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

विविध समाचार

बुजुर्गों को अब घर पर मिलेगी जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री की सुविधा-नीतीश कुमार

पटना ०९/०३ (संवाददाता): बिहार के मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य के 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को उनके घर पर ही जमीन या ज़्लैट की निबंधन (रजिस्ट्री) सुविधा उपलज़्ध कराने का ऐलान किया। यह सुविधा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा संचालित चलंत निबंधन इकाई (मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट) के माध्यम से निश्चित समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएगी, जिसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह नयी व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। मुज़्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एज़्स' पर पोस्ट कर बताया कि कई बार यह देखा गया है कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को जमीन या ज़्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर उन्हें सहूलियत देने और अनावश्यक परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने के इच्छुक लोगों को कई बार संबंधित भूमि की अद्यतन जानकारी उपलज़्ध नहीं हो पाती। इसे ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री से पूर्व भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी क्रेता और विक्रेता दोनों को उपलज़्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है।

इसके तहत आवेदकों के अनुरोध पर निबंधन विभाग अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता को उपलज़्ध कराएगा। इससे आवेदकों को जमीन के बारे में सही और प्रामाणिक जानकारी मिल सकेगी। मुज़्यमंत्री ने कहा कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नयी सरकार के गठन के बाद 'सात निश्चय-3' कार्यक्रमों को लागू किया गया है, जिनका उद्देश्य बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है।

'सात निश्चय-3' के अंतर्गत सातवां निश्चय 'सबका सज़्मान-जीवन आसान' (ईज ऑफ लिविंग) है, जिसका मुज़्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और अधिक सरल बनाना है। इसी दिशा में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल राज्य के 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। साथ ही भूमि की अद्यतन जानकारी उपलज़्ध कराने की व्यवस्था से सभी नागरिकों को लाभ होगा। मुज़्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था के संबंध में अन्य विशिष्ट सुझाव देने के इच्छुक लोग 19 जनवरी 2026 तक अपने बहुमूल्य सुझाव निर्धारित माध्यमों से भेज सकते हैं।

लंबे समय से ममता बनर्जी का चुनाव कैंपेन मैनेज कर रही है आई-पैक-उदित राज

मुंबई ०९/०३ (संवाददाता): तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की इलेज़्शन मैनेजमेंट कंपनी 'आई-पैक' के प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी से सियासत गर्म है। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने रविवार को अपनी प्रतिक्रिया दी।

कांग्रेस नेता उदित राज ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, आई-पैक लंबे समय से ममता बनर्जी का चुनाव कैंपेन मैनेज कर रही है। वहां का सारा डेटा और अंदर की जानकारी ममता बनर्जी और उनकी टीम की है। यह प्राइवेट है। ज़्या वे सज़्जियां बेच रहे हैं या किराने की दुकान चला रहे हैं? नहीं। आई-पैक सिर्फ टीएमसी का काम कर रहा है। वे वहां सिर्फ टीएमसी का डेटा चुराने और परेशानी खड़ी करने गए थे। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के केरल पर दिए हालिया बयान पर निशाना साधा। उदित राज ने अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, उनकी जिंदगी झूठ और नफरत पर बनी है। केरल शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बहुत आगे है।

यह कुछ इंडेज़्स में कई देशों से भी बेहतर प्रदर्शन करता है। अगर भाजपा वहां सज़ा में आती है, तो केरल उज़र प्रदेश या गुजरात जैसा राज्य बन सकता है। उदित राज ने कहा, वे जिस गुजरात मॉडल को बढ़ावा देते हैं, वह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में फेल हो गया है, और अगर इसे केरल में लागू किया गया, तो यह राज्य ने जो तरक्की हासिल की है, उसे नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा, वे हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेले बिना सफल नहीं हो सकते। वे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते।

उन्होंने दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वह पूरा नहीं हो सका। विदेश से काला धन भी नहीं आ सकता।卐 उन्होंने कहा, 卐केदारनाथ में 200 किलोग्राम से ज्यादा सोना शामिल था, फिर भी जांच ज़्यों नहीं हो रही है? उज़राखंड में मंदिर के पास करीब 220 किलोग्राम सोना था, फिर भी कोई जांच की मांग नहीं कर रहा है। ज़्योंकि चोरी उनके राज्य में हुई है, इसलिए वे कहेंगे कि यहां की सरकार उनकी सरकार से बेहतर है।

एचआईवी के बढ़ते मामलों से हड़कंप, बिहार के एक जिले में 7400 से ज्यादा एचआईवी पॉजिटिव, 400 बच्चे भी संक्रमित

सीतामढ़ी ०९/०३ (संवाददाता): बिहार के सीतामढ़ी जिले में एचआईवी के मामलों में तेजी से और चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। जिला अस्पताल के एआरटी केंद्र के अनुसार, अब तक लगभग 7,400 एचआईवी पॉजिटिव मरीज पंजीकृत किए गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 400 से अधिक बच्चे हैं, जिन्हें यह संक्रमण अपने माता-पिता से मिला है। एचआईवी संक्रमित बच्चों की उच्च संज़्या ने स्वास्थ्यकर्मियों के बीच चिंता बढ़ा दी है।

डॉज़्टरों का कहना है कि ये मामले मुज़्य रूप से उन परिवारों से संबंधित हैं जहां माता-पिता में से एक या दोनों एचआईवी पॉजिटिव हैं, जिसके परिणामस्वरूप जन्म के समय ही संक्रमण फैल जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एआरटी सेंटर के चिकित्सा अधिकारियों ने स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है और संक्रमण के बारे में सीमित जन जागरूकता को इस वृद्धि का कारण बताया है। सहायक सिविल सर्जन और एचआईवी नोडल अधिकारी, जे जावेद ने बताया कि अन्य जिलों में हमसे अधिक एचआईवी के मामले हैं। यह खांसी से फैलने वाली बीमारी नहीं है। यह रक्त आधान या एक ही सुई से इंजेज़्शन लगने से फैलती है। उन्होंने कहा कि आज स्कूलों में एड्स और एचआईवी के बारे में पढ़ाया जा रहा है... बेतिया, मोतिहारी और मुजज़्फरपुर की स्थिति हमसे भी बदतर है... लगभग 250 से 300 मरीज प्रतिदिन दवा लेने हमारे पास आते हैं; उपचारधीन मरीजों की कुल संज़्या 6,707 है। यह आंकड़े 2012 से अब तक के हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में जागरूकता अभियान तेज कर दिए हैं। एआरटी केंद्र नए सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम शुरू कर रहा है और स्वास्थ्य टीमें स्थानीय गांवों में एचआईवी जांच शिविर आयोजित करने की तैयारी कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले और पूरे राज्य को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। उनका कहना है कि सुरक्षित यौन संबंध, दूषित सुइयों के खतरे और नियमित एचआईवी जांच के महत्व के बारे में समय पर जागरूकता फैलाना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक है। अधिकारियों का मानना ??है कि व्यापक जन जागरूकता और नियमित जांच के बिना सीतामढ़ी में बढ़ते मामलों की स्थिति आने वाले महीनों में और बिगड़ सकती है।

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, उज़र प्रदेश समेत छह राज्यों में बढ़ी एसआईआर की समयसीमा, जारी हुआ नया शेड्यूल

नयी दिल्ली ०९/०३ (संवाददाता): भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को कहा कि वह उज़र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तारीखों में संशोधन कर रहा है।

चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छज़्ीसगढ़, उज़र प्रदेश और अंडमान और निकोबार में मतदाता सूची की एसआईआर (स्ढ्क्र) अनुसूची में संशोधन किया गया है। संबंधित मुज़्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के बाद चुनाव निकाय ने एसआईआर के लिए एक संशोधित कार्यक्रम जारी किया।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात को अब अपनी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) रिपोर्ट 19 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) तक जमा करनी होगी, जो पहले 14 दिसंबर, 2025 (रविवार) थी। मध्य प्रदेश, छज़्ीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए भी समय सीमा बढ़ा दी गई है, और नई जमा करने की तिथि 23 दिसंबर, 2025 (मंगलवार) निर्धारित की गई है, जो पहले की 18 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) की समय सीमा का स्थान लेगी। उज़र प्रदेश को अब अपनी एसआईआर रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2025 (बुधवार) तक जमा करनी होगी, जो पहले 26 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) थी।

भारत निर्वाचन आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (स्ढ्क्र) का दूसरा चरण चला रहा है। स्ढ्क्र का पहला चरण बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले सितंबर में पूरा हो गया था। यह प्रक्रिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छज़्ीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उज़र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को कवर करती है।

इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं। असम में भी 2026 में चुनाव होने हैं, जहां मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की गई है। इसे %विशेष संशोधन% कहा जा रहा है। अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची का अंतिम स्ढ्क्र 2002 और 2004 के बीच हुआ था, और उन्होंने अपने-अपने राज्यों में हुए अंतिम स्ढ्क्र के अनुसार वर्तमान मतदाताओं का मानचित्रण लगभग पूरा कर लिया है। स्ढ्क्र का मुज़्य उद्देश्य जन्मस्थान की जांच करके विदेशी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। बांग्लादेश और ज़्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों पर की जा रही कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण हो जाता है।

उनके हाथ कांप रहे थे, वे बहुत मानसिक दबाव में हैं..., राहुल गांधी ने फिर गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना

नयी दिल्ली ०९/०३ (संवाददाता): लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर अपना हमला जारी रखा, जिन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस के दौरान कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की थी। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने उनके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी कल बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, उनके हाथ कांप रहे थे... वे बहुत मानसिक दबाव में हैं। यह सबने कल देखा। मैंने उनसे जो भी पूछा, उन्होंने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। मैंने उन्हें सीधे तौर पर चुनौती दी है कि वे मैदान में आएं और संसद में मेरी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। मुझे कोई जवाब नहीं मिला।एक अन्य कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वह नहीं दिखी। हरियाणा में जो हुआ, उन्होंने उसके असली सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस पर आरोप लगाए। आज जो हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर, भाजपा ने कांग्रेस और लोकसभा के विपक्ष के नेता पर %हिट एंड रन% की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद पर हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी हिट एंड रन का फॉर्मूला अपनाते हैं... जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं, तो वे बाहर चले जाते हैं, यही उनकी लोकतंत्र है। उनमें सच सुनने की हिज़्मत नहीं है। कल केंद्रीय गृह मंत्री की बात सुनकर उन्हें बुरा लगा। मेरा मानना ??है कि राहुल गांधी को यह आदत छोड़नी होगी... गृह मंत्री के भाषण से पूरा नेहरू परिवार बिखर गया।बुधवार को लोकसभा में तनाव तब बढ़ गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच वोट चोरी के आरोपों पर तीखी बहस हुई। गांधी ने बार-बार शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी, जिसमें मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावे भी शामिल थे। शाह ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, 卐संसद उनकी मर्जी से नहीं चलेगी,卐 और जोर देकर कहा कि वे सभी सवालों का जवाब अपने क्रम में देंगे। शाह ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का भी बचाव किया और इसे मतदाता सूचियों को 卐शुद्ध卐 करने की एक आवश्यक प्रक्रिया बताया। विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे जीतने पर चुनाव आयोग की प्रशंसा करते हैं और हारने पर उसकी आलोचना करते हैं। यह टकराव शाह के जवाब के दौरान विपक्षी सांसदों के सदन से बाहर चले जाने के साथ चरम पर पहुंच गया, जिसके कारण लोकसभा को स्थगित करना पड़ा।

पाक सेना का भरोसेमंद, सऊदी अरब में गुप्त मिशन पर भी भेजा गया था, तहव्वुर राणा ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा

नयी दिल्ली ०९/०३ (संवाददाता):26/11 मुंबई आतंकी हमलों के पीछे मुज़्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर हुसैन राणा ने चौंकाने वाले दावे करते हुए खुलासा किया है कि वह पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद ऑपरेटिव था और उसे सऊदी अरब में एक गुप्त मिशन पर भेजा गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 26/11 आतंकी हमले से संबंधित मामले में एनआईए की हिरासत में मौजूद तहव्वुर राणा से पूछताछ की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले से जुड़ी कई जानकारियां पहले से ही आधिकारिक जांच रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि तहव्वुर राणा अपने पहले के बयानों पर मानसिक रूप से अड़ा हुआ है। अधिकारी ने कहा कि वह पुलिस को जानकारी दे रहा है लेकिन उसके बात करने का तरीका भी उसकी कट्टरपंथी विचारधारा को दर्शाता है। राणा ने दावा किया कि वह पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद ऑपरेटिव था और इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के दौरान उसे सऊदी अरब में एक गुप्त मिशन पर भेजा गया था, जिससे पाकिस्तान की सेना के लिए उसके रणनीतिक महत्व पर प्रकाश पड़ा। उसने कहा कि उसने 1986 में आर्मी मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और फिर क्वेटा में कैप्टन (डॉज़्टर) के पद पर नियुक्त हुआ। राणा ने सिंध, बलूचिस्तान, बहावलपुर और सियाचिन-बलोतरा सेज़्टर सहित पाकिस्तान के संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में काम करने का उल्लेख किया। उसने अज़्दुल रहमान पाशा, साजिद मीर और मेजर इकबाल जैसे प्रमुख 26/11 साजिशकर्ताओं को जानने की बात स्वीकार की, जो सभी पाकिस्तान से जुड़े थे और मुंबई हमलों में शामिल थे। राणा हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और पश्तो सहित कई भाषाओं में पारंगत है। उन्होंने खुलासा किया कि डेविड हेडली, जो कि अन्य मुज़्य आरोपी है, ने 2003 और 2004 के बीच लश्कर-ए-तैयबा के साथ तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया था। हालांकि, उसे सभी पाठ्यक्रमों के नाम याद नहीं हैं। मुंबई इमिग्रेशन सेंटर के बारे में पूछे जाने पर राणा ने दावा किया कि यह उसका अपना विचार था, हेडली का नहीं। उसने यह भी कहा कि हेडली को भेजे गए पैसे का उद्देश्य व्यावसायिक खर्च था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि मुंबई कार्यालय में ग्राहकों को आकर्षित करने में कठिनाइयाँ थीं।

हमलोग तो पीएम बनाना चाहते थे, सीएम ही रह गए नीतीश-अखिलेश

लखनऊ ०९/०३ (संवाददाता): समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार कहा कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को पूरा समर्थन देगी। इसके साथ ही अखिलेश ने नीतीश कुमार और पर तंज भी कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेंगे लेकिन सीएम नहीं बनाएंगे। हम तो नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहते हैं। उज़र प्रदेश के पूर्व मुज़्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए बिहार के मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उन्हें फिर से मुज़्यमंत्री बनाने का कोई इरादा नहीं है। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार जी के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें फिर से मुज़्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम एक बार उन्हें प्रधानमंत्री पद का उज़्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन अब देखिए- वह मुज़्यमंत्री पद से ही 'रिटायर' हो जाएंगे। भाजपा उन्हें 'रिटायर' होने के लिए मजबूर करेगी।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

मौसम के अनुरूप बनाएं सब्जियों का फसल चक्र

बेल वाली सब्जियों को मुख्यत क्युकर बिटेसी' यानी खीरा जाति की सब्जियों में रखा जाता है। इस वर्ग की सब्जियों में बीज कड़े होते हैं और उनके अंकुरण में काफी समय लगता है। इसीलिए बेल वाली सब्जियों की अगेती फसल लेने के लिये सब्जी उत्पादक प्लास्टिक की थैलियों में खाद युक्त मिट्टी भरकर उसमें बीज बोते हैं और जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है तो उसे खेत में लगा देते हैं।

टिन्डा

इसके लिये अनुकूल तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस से 26.5 डिग्री सेल्सियस है। फसल न्यूनतम 18.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस पर होती है। मौसम में नमी अगर अधिक हो तो पत्तियों में रोग की संभावना रहती है और फल उच्चकोटि के नहीं मिल पाते। बीज अंकुरण के लिये 21 डिग्री सेल्सियस से 29.5 डिग्री सेल्सियस का अनुकूल तापक्रम माना गया है। टिंडे को गर्म मौसम की आवश्यकता होती है।

खीरा और लौकी

अनुकूल तापक्रम 18.5 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम 15.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर इसकी फसल अच्छी पाई गई है। पकने की अवस्था पर न्यून तापक्रम का अच्छा प्रभाव पड़ता है और अधिक नम मौसम में पत्तियों के रोग की संभावना अधिक होती है। अधिक तापक्रम और लंबे दिन में नर फूल ज्यादा आते हैं और मादा फूलों की संख्या कम होने के कारण उपज कम मिलती है। यदि भूमि का तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस हो तो बीज का अंकुरण नहीं होता।

लौकी के लिये नम और गर्म जलवायु उत्तम रहती है। मध्यम जलवायु में इस फसल को वर्ष भर उगाया जा सकता है। भारी वर्षा और बदली वाला मौसम व्याधि और कीड़ों के प्रकोप को बढ़ा देते हैं। लम्बे मौसम की फसल होने के कारण फरवरी में बोई गई फसल बरसात के मौसम तक चलती रहती है। अधिक गर्मी से इस फसल पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

करेला, घिया व आरा तोरी

इन फसलों के लिये जलवायु लौकी के समान रहती है। ये फसलें शीतकालीन मौसम कुछ अधिक बरदाश्त कर लेती हैं किंतु अधिक गर्मी में फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।काशीफल 80 से 120 दिन की फसल है। फूल 60 से 80 दिन में आते हैं और फल पकने में 60 दिन लग जाते हैं। कद्दू या पीला कोहड़ा के लिये 18.5 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त है। और इस तापक्रम में फल अच्छे लगते हैं। इन सब्जियों के लिये न्यूनतम तापक्रम 15.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29.5 डिग्री सेल्सियस सर्वोत्तम माना गया है।

ककड़ी

इसके लिये गर्म मौसम की जरूरत पड़ती है। तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस से 26.5 डिग्री सेल्सियस पर्याप्त है, पर 32 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में भी फसल उगाई जा सकती है। अन्य बेल वाली सब्जियों में परवल के लिये अधिक गर्म व नमी तथा वर्षा वाले क्षेत्र सर्वोत्तम होते हैं। इसीलिए परवल की बेलों को पान के बरेजों में सफलतापूर्वक बढ़ने का मौका मिलता है। चिचिड़ा भी गर्म मौसम की बेल वाली सब्जी है। इसे कम तापमान पर पहाड़ों पर भी उगाया जा सकता है। बिहार और बंगाल के इलाकों में जहां पाले से क्षति होने की संभावना कम होती है। चिचिड़ा को अक्टूबर से नवम्बर तक भी लगाया जा सकता है।

ये निम्न प्रकार है

(क) मूली (जुलाई-अगस्त) - मटर (अक्टूबर-मार्च) करेला (मार्च-जून).

(ख) अदरक (जून-अक्टूबर)- पालक/ मैथी/ धनिया/ सौआ/ सौंफ (अक्टूबर से जनवरी) खीरा जाति की सब्जियाँ (फरवरी-जून.

(ग) बैंगन (अगस्त-मार्च),- टिन्डा (मार्च-अगस्त)

(च) लोबिया (जुलाई-नवम्बर)- करेला (जनवरी-जून)

(छ) खीरा (जुलाई-सितम्बर) फूलगोभी (अक्टूबर-जनवरी)-कद्दू या काशी फल (फरवरी-जुलाई).

(झ) भिंडी (जुलाई-अक्टूबर)-फरासबीन (अक्टूबर-फरवरी)-टिन्डा (मार्च-जून)

(य) देसी गाजर (अगस्त-दिसम्बर)-लौकी (जनवरी-जुलाई)

(र) शलजम (सितम्बर-जनवरी) - पालक (फरवरी-अप्रैल)- खीरा (अप्रैल-जुलाई)

(ल) टिन्डा (जून-अगस्त)- गांठ गोभी (अक्टूबर-फरवरी) पालक (फरवरी-अप्रैल)- तोरई (अप्रैल-जून)

यूरिया की आधी मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा के साथ बीज लगाने के 2 से 3 दिन पूर्व थालों में अच्छी तरह मिला दें। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा एक महीने की खड़ी फसल में 20 से 30 से.मी. की दूरी पर थालों में देने की सिफारिश की जाती है। इसके बाद मिट्टी चढ़ावें और गुड़ाई भी करें और सिंचाई करें (यूरिया प्रयोग करने के 2-3 दिन बाद).

उपयुक्त फसल चक्र

उत्तरी भारत में मौसम की अनुकूलता के अनुसार ग्रीष्मकाल में एक वर्षीय फसल चक्रों में बेलवाली सब्जियों को सफलता पूर्वक शामिल किया जा सकता है।

खेत से लेकर भण्डारण तक आलू की देखभाल

खुदाई के समय रखी जाने वाली मुख्य सावधानियाँ

- खुदाई के समय अधिक नमी न हो. क्योंकि अधिक नमी होने पर कन्द पर मिट्टी चिपकेगी.
- तुरंत खोदे गए आलू को ज्यादा ऊंचाई से ढेर पर न फेंकें.
- खोदे गए आलू को दो घंटे तक इकट्ठा न करें जिससे आलू का छिलका मजबूत हो जाये और मिट्टी कम चिपके.
- आलू को खुदाई पूर्व अंगूठे से रगड़कर देख लें कि छिलका उतर तो नहीं गया. और यदि छिलका कच्चा हो तो कुछ दिन बाद खोदें.
- मैदानी क्षेत्र में बीज के लिए खुदाई फरवरी माह में खुले मौसम में करें क्योंकि अधिक तापमान काला गलन रोग की संभावना बढ़ जाती है.
- आलू की खुदाई आधुनिक मशीन से करने कंद सुरक्षित निकलते हैं जबकि खुरपी व फावड़े से कंद छिल जाते हैं.
- बीज वाली फसल को ऊपर से पौधे को काट देते हैं तथा कटाई के एक सप्ताह पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए, जिससे कंद का छिलका नरम न रहे और आलू खराब न हो.
- बीज के लिए बोई गई फसल को मध्य जनवरी तक पत्तियों की कटाई कर दें.
- पिछेती झुलसा की संभावना वाले आलू को अलग कर देना आवश्यक है जिससे अगली वर्ष बुवाई न हो.

आलू का ढेर बनाते समय सावधानियाँ

- ढेर बनाते समय ऊपर से सीधा न फेंकें.
- आलू की खुदाई के बाद 10-15 दिन छिलका मजबूत होने तक ढेर में सड़न पैदा न हो.
- आलू का ढेर छाया में बनायें जिसे पुआल या चटाई से अच्छी तरह ढंक दें.
- आलू के ढेर की ऊंचाई डेढ़ मीटर से अधिक न रखें तथा उसकी चौड़ाई 4-5 मीटर रखें लम्बाई कितनी भी रख सकते हैं.

छटाई (ग्रेडिंग) करते समय सावधानियाँ -

- आलू को अच्छी तरह देखकर उसके वजन व आकार के अनुरूप श्रेणियों में बांटने को ही ग्रेडिंग कहते हैं. ऐसा करने से आलू के अच्छे दाम मिलते हैं जिसके लिए वजन निम्नानुसार रखना अच्छा माना जाता है.

(अ) बड़े आलू- जिनका वजन 125 ग्राम से ज्यादा हो.

(ब) मध्यम आलू- जिनका वजन 80 से 125 ग्राम हो.

(स) बीच के आलू- जिनका वजन 40 से 80 ग्राम हो.

(द) छोटे आलू- जिनका वजन 25 से 40 ग्राम हो इनके अलावा जिन कंदों का वजन 25 ग्राम से कम हो बुवाई के लिए उपयोग में लेना चाहिए.

आलू कंदों का उपचार करते समय सावधानियां

- बीज के लिए रखे जाने वाले आलू को साफ पानी से धोना आवश्यक है जिससे मिट्टी न लगी रहे इसके बाद एमिसान रसायन के 0.25ज् घोल में 20 मिनिट तक डुबोयें.
- उपचारित बीज को सुखाकर बोरियों में भरें परंतु ध्यान रखें कि तेज धूप में सुखायें क्योंकि बीज की आंखें प्रभावित हो सकती हैं.
- उपचारित करने वाले आदमी को हाथों में दस्ताने पहनना चाहिए तथा घाव वाले व्यक्ति उपचार का कार्य न करें.
- शीत ग्रह में भंडारण के पूर्व बीज को उपचारित कर ही रखें.

खुदाई के बाद भंडारण तक पहुंचने और पैकिंग में रखी जाने वाली सावधानियाँ -

- आलू के कंद को अच्छी तरह देख लें कि कम से कम खरोंच हो.
- आलू भंडारण में भेजे जाने वाले बोरों को ऊंचाई से न फेंकें. आलू कट-फट सकते हैं.
- पैकिंग पूर्व आलू को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए.
- पैकिंग किये जाने वाला स्थान हवादार हो.

भण्डारण में रखी जाने वाली सावधानियां -

- अपनी फसल के उत्पादन को देखते हुए पहले शीतग्रह में आरक्षण ले लें जिससे समय पर सुविधानुसार भंडारित हो सकें.
- आलू को शीतग्रह में पहुंचने से पूर्व कटे-फटे आलू अलग होना आवश्यक है.
- आलू बोरी की कसकर सिलाई होना चाहिए अन्यथा ढीली बोरियों में आलू का छिलका उतरने का खतरा रहता है.
- भण्डारण में उपयोग किये गये बोरे नये होने चाहिए.
- आलू की बोरी पर लिखें कि उपचारित की गई है और किस्म का नाम भी अंकित करें.
- उपचारित बीज को कभी भी खाने में उपयोग न करें.
- प्रयास करें कि मार्च के मध्य तक आलू की ग्रेडिंग कर शीत ग्रह में भंडारित कर दें.

- उपचारित बीज की पैकिंग के बाद धूप में न रखें.
- उपचार दवाई को बच्चों व पशुओं की पहुंच से दूर रखें.
- बीज उपचार रसायन के डिब्बों को खाने वाली वस्तुओं में उपयोग न करें.
- बीजों उपचार में लगे व्यक्ति को बाद में साबुन से हाथ धोना चाहिए.

कद्दूवर्गीय सब्जियां और बेकाबू कीट-बीमारियां

हमारे देश में मुख्य रूप से लौकी, करेला, कद्दू, खीरा, तरबूज, खरबूज, घीया, टिण्डा, परवल को ग्रीष्म व वर्षाऋतु में उगाते हैं. इन सब्जियों पर रोग व कीड़ों के आक्रमण से काफी नुकसान होता है यदि इन व्याधियों को समय पर नियंत्रित कर दिया जाये तो उत्पादन को 15-20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. कद्दूवर्गीय सब्जियों में लगने वाले प्रमुख रोग कीट व उनका नियंत्रण इस प्रकार किया जा सकता है.

कद्दूवर्गीय सब्जियों के प्रमुख कीट

कद्दू का लाल गिडार- लाल रंग का उड़ने वाला यह कीट शिशु पौधों की पत्तियों को खाकर छलनी जैसे छिद्र कर देता है जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है फलों में भी यह छेदकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है कीट नियंत्रण हेतु मैलाथियान 50 ई.सी. या ऐसीफेट 75 एस.पी. के 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिए.

फलवेधक मक्खी-

कीट का मैगट फलों एवं बेलों को खाते हैं जिससे बेल में गांठे बन जाती है. मादा मक्खी अपने अंडरोपक की सहायता से फलों की ऊपरी सतह में छिद्र करने के पश्चात अंडरोपण करती है जिससे वहां फल की सतह के ऊपर रस जमकर एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है और अंत में फल सड़ जाते हैं. कीट नियंत्रण हेतु मैलाथियान या डाइमिथियेट 30 ई.सी. का 0.1 प्रतिशत के घोल का छिड़काव करना चाहिए.

माहू- इस कीट के शिशु व वयस्क दोनों पत्तियों से रस चूसकर उन्हें कमजोर करते हैं साथ ही विशेष प्रकार का मधुस्राव पत्तियों पर छोड़ते हैं जिस पर बाद में फफूंद लग जाने से यह स्थान काला रंग का हो जाता है. यह कीट मोजेक रोग को रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे तक फैलाते हैं नियंत्रण हेतु ऑक्सीडिमेटान मिथाइल 25 ई.सी. अथवा डाइमिथियेट 30 ई.सी. 1.0 मि.ली. प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिये.

कद्दूवर्गीय सब्जियों के प्रमुख रोग

चूर्णीफफूंद या भभूतिया रोग- इस रोग का प्रकोप मुख्य रूप से खीरा, लौकी, खरबूज में होता है. रोग की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों की निचली सतह पर गोल-गोल सफेद धब्बे बनते हैं तथा रोग के उग्र होने पर ये धब्बे भूरे हो जाते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद चूर्ण बिखरा रहता है, बाद में पत्तियां सड़ जाती हैं आर्द्र व ऊष्ण जलवायु में यह रोग अधिक लगता है रोग नियंत्रण हेतु कवकनाशी-केराथेन 0.5 प्रतिशत अथवा सल्फेक्स 0.2 प्रतिशत का छिड़काव करना चाहिए.

मृदुरोमिल आसिता

लौकी, खीरा, खरबूज, करेला आदि में सर्वप्रथम पत्तियों के ऊपरी सतह पर पीले धब्बे बनते हैं तथा निचली सतह पर रूई जैसी वृद्धि दिखाई देती है. रोग नियंत्रण हेतु 0.3 प्रतिशत का छिड़काव 10 दिन के अंतर से करना चाहिए.

आल्टरनेरिया झुलसन रोग-

आल्टरनेरिया झुलसा रोग की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों पर छोटे-छोटे धब्बे बनते हैं जो बाद में संख्या व आकार में बढ़कर मिलकर पूरी पत्ती को झुलसा देते हैं. नियंत्रण हेतु मेंकोजेब 0.3 प्रतिशत अथवा कार्बेन्डाजिम 0.1 प्रतिशत का छिड़काव करना चाहिए.

मोजेक- विषाणुजनित इस रोग में पत्तियों पर पीलापन, सिकुड़न, इंटरनोड का छोटा होना प्रदर्शित होता है इस रोग का संचरण माहू नामक कीट द्वारा होता है रोग से बचाव हेतु वाहक कीट का नियंत्रण आवश्यक है. अतः ऑक्सी मिथाइल डिमेटान 25 ई.सी. या डाईमिथियेट 30 ई.सी. 0.1 प्रतिशत का छिड़काव करें. प्रारंभिक अवस्था में रोगित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए.

कलिंग समाचार

संपादकीय

मंगलवार 10 मार्च 2026

फिर निशाने पर जेएनयू

देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर एक बार फिर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हमलावर हैं। इस संस्थान को टुकड़े-टुकड़े गैंग का अड्डा बताया जा रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद से जेएनयू भाजपा और संघ समर्थकों के निशाने पर रहता आया है। खासकर संस्थान के जो छात्र वामपंथी विचारों के हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से देशद्रोही ठहराने की कोशिशें की जाती हैं। वही कोशिशें सोमवार से फिर शुरु हो चुकी हैं। दरअसल सोमवार 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि अन्य पांच सह आरोपियों को जमानत दे दी गई है। जबकि छह साल पहले 2020 में जेएनयू के इतिहास की सबसे बड़ी हिंसक घटना 5 जनवरी को हुई थी। जिसमें विवि परिसर में नकाबपोश लोगों की भीड़ ने हॉस्टलों में घुसकर छात्रों पर लाठी, पत्थर और लोहे की रॉड से हमला किया था। इस हमले में तत्कालीन छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष सहित कम से कम 28 लोग घायल हुए थे, इसमें दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे कि आखिर उसके रहते इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। आज तक उस घटना के असल दोषियों को सजा नहीं हुई है। इसी पर हर साल जेएनयू में छात्र इकट्ठा होकर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। सोमवार रात भी छात्र एकत्र हुए और जेएनयू परिसर में नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई। इसमें उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल की भी खबरें हैं। यह सही है कि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में कट्टर से कट्टर विरोधी के लिए भी मर्यादा के दायरे में रहकर शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन फिर यह संतुलन दोनों पक्षों से अपेक्षित होता है। अभी केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ लोगों ने जेएनयू को टुकड़े-टुकड़े गिरोह का अड्डा बना दिया है। राहुल गांधी, टीएमसी, क युनिस्ट जैसे लोग इस गिरोह का हिस्सा हैं... ये लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते। उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पाकिस्तान जैसी मानसिकता रखने वालों को भारत की जनता ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।सरकार के विरोध में जब भी कोई आवाज शैक्षणिक परिसरों से उठती है, उसे दबाने या फिर गलत साबित करने की कोशिशें शुरु हो जाती हैं। जेएनयू में तो अब होली-दीवाली जैसे मौकों पर भी खान-पान के नाम पर ही झड़पें होने लगी हैं। एक बार तो विजयादशमी पर एबीवीपी ने रावण दहन में अफजल गुरु, उमर खालिद और शरजील इमाम के चित्र लगाकर पुतला जलाए, जिस पर वामपंथी समूहों ने इसे इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। ऐसी तमाम झड़पों और हिंसक घटनाओं के पीछे मकसद यही है कि किसी भी तरह विश्वविद्यालय परिसर को हिंदुत्ववादी गतिविधियों का अड्डा बनाया जाए। सोमवार के विरोध के बाद ही एबीवीपी ने कहा है कि वह इस विरोध प्रदर्शन की शिकायत पुलिस में करेगा। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा है कि छात्र 5 जनवरी, 2020 को परिसर में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए हर साल विरोध प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया, विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं है। वे किसी को लक्षित करते हुए नहीं थे। बता दें कि जेएनयू में वामपंथी समर्थित छात्र संगठन का कब्जा है और यह भी संघ और भाजपा के लिए एक बड़ी कसक है कि उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद जेएनयू में वाममोर्चा पस्त नहीं हो रहा है। जेएनयू में सोमवार रात लगे नारों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि आप लोगों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का एक तरीका होता है। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने पूछा है कि क्या यह चुनिंदा आक्रोश है? हां, लोग स्वाभाविक रूप से गुस्से में हैं। हममें से कई लोगों को भी लगता था कि शरजील और उमर को जमानत मिल जानी चाहिए थी। पांच साल से अधिक समय बीत चुका है और मुकदमे के नाम पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

वेनेजुएला के काले सोने के भंडार पर डोनाल्ड ट्रंप का जोखिम भरा दांव

के रवींद्रन

अर्थव्यवस्था के अलावा, राजनीतिक और सुरक्षा का माहौल निवेशकों के लिए हिफाजत के ट्रंप के भरोसे को परखेगा। निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अचानक हुए सैन्य कार्रवाई और उसके बाद वेनेजुएला की तेल बिक्री पर अनिश्चितकाल तक के लिए नियंत्रण के ट्रंप प्रशासन के दावे की दुनिया भर में कड़ी आलोचना हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खनिज तेल (काला सोना) के मामले में वेनेजुएला पर ज़्यादा ध्यान देना, अमेरिकी नीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार को बनाने में इस दक्षिण अमेरिकी देश की पेट्रोलियम संपदा की रणनीतिगत अहमियत को दिखाता है। दशकों से, वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार, जो कभी उसकी अर्थव्यवस्था की नींव थे, कुप्रबंधन, पाबंदियों और अवसंरचना की कमी की वजह से खराब हो गए हैं।

फिर भी ट्रंप के हालिया काम— सुरक्षा का भरोसा देकर दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों से वेनेजुएला लौटने को कहने से लेकर वेनेजुएला के तेल प्रवाह पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा करने तक— उन संसाधनों का इस्तेमाल करने की एक सोची-समझी कोशिश दिखाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह दांव खनिज तेल उत्पादन को 21वीं सदी के शुरुआती लेवल, लगभग 30 लाख बैरल प्रतिदिन पर वापस ला सकता है? अगर हां, तो कितनी तेज़ी से और किस कीमत पर?

वेनेजुएला के पास किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा तेल के पक्के भंडार हैं, जिसका अंदाज़ा लगभग 303अरब बैरल है। यह आंकड़ा दुनिया भर के कच्चे तेल के भंडार का लगभग 17 प्रतिशत है, जो बड़े उत्पादक देशों को बहुत पीछे छोड़ देता है और तेल बाज़ारों पर लंबे समय तक असर डालता है। पिछली सरकारों के तहत, जिसमें 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत भी शामिल है, वेनेजुएला का रोज़ का कच्चे तेल का उत्पादन 30 लाख बैरल के करीब या उससे ज़्यादा था, जिससे यह दुनिया के बड़े खनिज तेल निर्यातकों में से एक बन गया। आज उसका उत्पादन गिरकर 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी कम हो गया है, जो इसकी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे कम निवेश, राजनीतिक उथल-पुथल, पाबंदियों, और सरकारी कंपनी पेट्रोलियोसडी वेनेजुएला एस.ए. की खराब हालत ने रोका है।

ट्रंप प्रशासन का तरीका भू-राजनीतिक दबदबे को निजी पूंजी के उनके आग्रह के साथ जोड़ता है। शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल और कोनोकोफिलिप्स के कार्यपालक अधिकारियों के साथ हाल की बैठक में, ट्रंप ने वेनेजुएला की खनिज तेल संपदा के साथ बड़े पैमाने पर फिर से जुड़ने को बढ़ावा दिया है, उनके कार्यसंचालन के लिए %पूरी हिफाजत और सलामती% का वादा किया है, और अमेरिकी सरकार के पूंजी के बिना कम से कम 100 अरब डालर के औद्योगिक निवेश की अपील की है। यह पेशकश खनिज तेल उत्पादन को फिर से शुरू करने की इच्छा और अमेरिकी हितों के लिए अच्छी शर्तों पर वेनेजुएला के कच्चे तेल को वैश्विक बाजार के साथ समेकित करने की इच्छा, दोनों को दिखाती है। यह इस क्षेत्र में चीनी और रूसी प्रभाव का मुकाबला करने सहित बड़े भूराजनीतिक मकसदों को भी पूरा करता है।

हालांकि, तेल कंपनियों से की गई अपील को नपी-तुली प्रतिक्रिया मिली है। शेवरॉन, जो पीडीवीएसए के साथ संयुक्त उपक्रम के ज़रिए वेनेजुएला में चल रहे संचालन वाली एकमात्र बड़ी अमेरिकी कंपनी है, ने अगले 18-24 महीनों में शायद 50 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाने की तैयारी जताई है, अगर नियामक और संचालन के हालात इजाज़त देंगे। लेकिन एक्सॉनमोबिल जैसी कंपनियां ज़्यादा सावधान रही हैं, और उसके नेतृत्व ने वेनेजुएला को बड़े कानूनी और वाणिज्यिक सुधारों के बिना निवेश करने लायक नहीं बताया है। पहले हुई ज़ब्ती और मुआवज़े के अनसुलझे दावों ने एक ऐसे देश को बड़ी रकम देने को लेकर डर बनाए रखा है जो लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। वेनेजुएला को 1970 के दशक के चरम उत्पादन जैसी स्थिति में वापस लाना सिर्फ़ एक प्रतीकात्मक उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। यह आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों को दिखाता है। विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा खनिज तेल क्षेत्रों और पाइप लाइनों में धीरे-धीरे सुधार अरबों डॉलर की पूंजी से किया जा सकता है, जिससे कुछ सालों में उत्पादन कई लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ सकता है। फिर भी, 30 लाख बैरल प्रति दिन उत्पादन तक पहुंचने के लिए— जो मौजूदा लेवल से तीन गुना से भी ज़्यादा है— शायद 50अरब डालर के अनुदार अनुमान से कहीं ज़्यादा लगातार निवेश की ज़रूरत होगी, जो शायद एक दशक या उससे ज़्यादा समय में सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह सिर्फ़ ड्रिलिंग और खनन सुविधाओं की पूंजी की कीमत को ही नहीं दिखाता, बल्कि ऊर्जा अवसंरचना, परिवहन, रखरखाव और ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले संस्थानिकतानेबाने में बड़े बदलाव की ज़रूरत को भी दिखाता है। वेनेजुएला के कच्चे तेल की प्रकृति इसे और मुश्किल बनाता है। देश का ज़्यादातर तेल भारी और खट्टा होता है, जिसके लिए घोलक रसायन और खास परिष्करण क्षमता की ज़रूरत होती है। हालांकि अमेरिकी खाड़ी तट के परिष्करण संयंत्र ऐसी श्रेणी को प्रसंस्कृत करने के लिए काफी अच्छी तरह से तैयार हैं, लेकिन भारी खनिज तेल की अर्थव्यवस्था दूसरी जगहों पर बनने वाले हल्के विकल्पों की तुलना में कम आकर्षक हैं। यह कारक, वैश्विक खनिज तेल की अस्थिर कीमतों और दूसरे इलाकों से प्रतिस्पर्धी आपूर्ति के साथ मिलकर, बड़ी तेल कंपनियों के लिए बिना किसी पक्की गारंटी और स्थिर वाणिज्यिक शर्तों के वेनेजुएला की गहरी समस्याओं में उतरने के लिए अल्पावधि वित्तीय प्रोत्साहन को कमजोर करता है। अर्थव्यवस्था के अलावा, राजनीतिक और सुरक्षा का माहौल निवेशकों के लिए हिफाजत के ट्रंप के भरोसे को परखेगा। निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अचानक हुए सैन्य कार्रवाई और उसके बाद वेनेजुएला की तेल बिक्री पर अनिश्चितकाल तक के लिए नियंत्रण के ट्रंप प्रशासन के दावे की दुनिया भर में कड़ी आलोचना हुई है। क्षेत्रीय नेता और अन्तरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक चेतावनी देते हैं कि इस तरह के दखल स प्रभुता को कमजोर करते हैं और पहले से ही कमजोर देश को अस्थिर करने का जोखिम उठाते हैं। जहां ट्रंप इस कदम को वेनेजुएला के लोगों के लिए फायदेमंद और ऊर्जा सुरक्षा का रास्ता बताते हैं, वहीं आलोचक इसे अनिश्चित नतीजों के साथ एक सामरिक संसाधन हड़पने के रूप में देखते हैं। ज़्यादा जानें विशेष रिपोर्ट सदस्यता मु य शीर्षक खेल समाचार राजनीति समाचार खेल उपकरण प्रमुख समाचार ई-पेपर डिजिटल मार्केटिंग सेवाएँ बॉलीवुड समाचार पत्रिका ई-पेपर सदस्यता अंदरूनी तौर पर, वेनेजुएला ढांचागत चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई रुकावटें हैं जिन्हें सिर्फ़ बाहरी पूंजी से हल नहीं किया जा सकता। दशकों तक कम निवेश और राजनीतिक दखलअंदाज़ी ने उस विशेषज्ञता और आवसंरचना को कमज़ोर कर दिया है जो कभी पीडीनीएसए के कार्यसंचालन के आधार थे। लगातार बिजली कटौती, ईंधन की कमी और बार-बार रिफाइनरी खराब होना सिस्टम की गहरी नाकामियों के लक्षण हैं जिनसे निवेशकों को निपटना होगा। मज़बूत प्रशासनिक सुधारों और भरोसेमंद कानूनी सुरक्षा के बिना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे औद्योगिक पुनर्जागरण के लिए ज़रूरी संसाधनों का निवेश करने में हिचकिचा सकती हैं। वेनेजुएला के खनिज तेल उत्पादन को फिर से शुरू करने के व्यापक नतीजे उसकी सीमाओं से कहीं आगे तक जाते हैं। अगर उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, तो वैश्विक तेल बाज़ारों में कीमतों पर नीचे की ओर दबाव दिख सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा लेकिन संभावित रूप से अन्य उत्पादकों, जिसमें अमेरिकी शेल ऑपरेटर भी शामिल हैं, के मुनाफ़े के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। बाज़ार में बड़ी मात्रा में वेनेजुएला के कच्चे तेल के आने से व्यापार प्रवाह भी बदल सकता है, खासकर अगर चीनी रिफाइनरियों के साथ संबंध- जो लंबे समय से वेनेजुएला के तेल के खरीदार हैं- बाधित या पुनर्निर्देशित होते हैं। ट्रंप की खनिज तेल-केंद्रित रणनीति में ऊंचे जोखिम और फायदे अनिश्चित हैं। इसका मकसद वेनेजुएला की भू-भौतिक संपदा का फ़ायदा उठाना और पश्चिमी गोलार्ध में भू-राजनीतिक गठबंधनों को फिर से आकार देना है। अगर यह सफल होती है, तो यह एक कमज़ोर क्षेत्र को फिर से मज़बूत कर सकती है, वेनेजुएला की एक ही वस्तु पर आर्थिक निर्भरता को कम कर सकती है, और ऊर्जा बाज़ारों पर अमेरिकी प्रभाव को मज़बूत कर सकती है। फिर भी, उत्पादन में सार्थक उछाल का रास्ता मुश्किल है, जिसके लिए न सिर्फ़ पूंजी बल्कि राजनीतिक स्थिरता, संस्थागत सुधार और वेनेजुएला सरकार और विदेशी निवेशकों दोनों की ओर से लगातार प्रतिबद्धता की ज़रूरत है।

प्रवासी भारतीय दिवस

अरुण कुमार डनायक

भारत पिछले कई वर्षों से विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया रेमिटेंस न केवल विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टार्टअप सहित छोटे व्यवसायों को भी आधार देता है। जून 2025 तक भारतीय बैंकों में एनआरआई जमा राशियां लगभग 3.6 बिलियन डॉलर रहीं, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में रेमिटेंस बढ़कर 135.46 बिलियन डॉलर पहुंच गया।

इतिहास की कुछ तिथियां केवल अतीत की स्मृति नहीं, भविष्य की दिशा भी तय करती हैं। 9 जनवरी ऐसी ही एक तिथि है, जब 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। राजनीतिक निराशा के दौर में उन्होंने देश का भ्रमण कर भारत की आत्मा को समझा और व्यापक जन-आंदोलन की नींव रखी। इसी ऐतिहासिक वापसी की स्मृति में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है—जो गांधीजी की विरासत और विदेशों में बसे भारतीयों के योगदान दोनों का सम्मान करता है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय वाला देश है। 1990 में जहां प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 66 लाख थी, आज विश्व भर में लगभग 3.5 करोड़ भारतीय रहते हैं, जिनमें करीब 1.6 करोड़ अप्रवासी भारतीय और लगभग 1.95 करोड़ विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। विभिन्न अनुमानों के अनुसार, अमेरिका में 55 लाख, संयुक्त अरब अमीरात में 36 लाख और मलेशिया में 28 लाख भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा अन्य देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय बसे हुए हैं। खाड़ी देशों में कुल प्रवासी भारतीयों का लगभग आधा हिस्सा निवास करता है। यूरोप और खाड़ी देशों में भारतीय कुशल एवं अर्ध-कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग के चलते श्रमिकों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही अब केवल आर्थिक विषय नहीं रह गई है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। आज भारत कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों में कौशल-आधारित श्रम सहयोग, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित आव्रजन को केंद्रीय विषय के रूप में आगे बढ़ा रहा है।

भारत पिछले कई वर्षों से विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया रेमिटेंस न केवल विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टार्टअप सहित छोटे व्यवसायों को भी आधार देता है। जून 2025 तक भारतीय बैंकों में एनआरआई जमा राशियां लगभग 3.6 बिलियन डॉलर रहीं, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में रेमिटेंस बढ़कर 135.46 बिलियन डॉलर पहुंच गया—पिछले वर्ष से करीब 14 प्रतिशत अधिक, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच प्रवासी भारतीयों के भरोसे और निरंतर योगदान को दर्शाता है।

प्रवासी भारतीयों ने विज्ञान और शिक्षा में वैश्विक नवाचार को बढ़ावा दिया—जैसे कल्पना चावला, सत्य नडेला और सुंदर पिचाई; राजनीति में ऋषि सुनक, अनिरुद्ध जगन्नाथ, महिला प्रवासियों ने व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया—जैसे इंदिरा नूयी, और मीरा नायर; वहीं रविशंकर, जुबिन मेहता जैसे कलाकारों ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के माध्यम से भारत की वैश्विक छवि को सशक्त किया। संकट की घड़ियों में प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भी स्पष्ट होती है—कोविड-19 के दौरान रेमिटेंस जीवनरेखा बना रहा, जबकि 2018 की केरल बाढ़ में खाड़ी देशों से व्यापक आर्थिक और राहत सहायता पहुंची। राष्ट्रीय स्वाभिमान के संकट में भी प्रवासी भारतीय भारत के साथ मजबूती से खड़े रहे। इसका सशक्त उदाहरण मई 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण हैं, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने अपनी परमाणु क्षमता का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रशासन ने ग्लेन संशोधन के तहत अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इस चुनौतीपूर्ण समय में वाजपेयी के आह्वान पर एनआरआई समुदाय ने रेमिटेंस बढ़ाया इससे विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिरता मिली और प्रतिबंध काफी हद तक निष्प्रभावी हुए। यह सहयोग आर्थिक ही नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और आत्मसम्मान के प्रति प्रवासी भारतीयों की गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण था।

भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने प्रवासी भारतीयों को विकास-यात्रा से जोड़ने के लिए कई पहलें की हैं। ओसीआई कार्ड ने वीज़ा-मुक्त यात्रा, संपत्ति स्वामित्व और व्यापारिक भागीदारी को आसान बनाया है, जबकि एनआरई/एनआरओ खाते और एफसीएनआर जमाएं सुरक्षित निवेश व कर रियायतें देती हैं। डिजिटल भारत के तहत यूपीआई के अंतरराष्ट्रीय विस्तार से विदेशी मोबाइल नंबरों के माध्यम से भी भारत में भुगतान और लेन-देन संभव हुआ है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों को सरल बनाकर निवेश, व्यापार और रेमिटेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान किया गया है। कर नियमों के अनुसार एनआरआई की वही आय भारत में कर योग्य मानी जाती है जो भारत में स्थित संपत्ति, व्यापार, सेवाओं या आय-स्रोत से उत्पन्न हो—जैसे संपत्ति के हस्तांतरण से पूंजीगत लाभ, भारत में दी गई सेवाओं का वेतन, भारतीय कंपनियों से लाभांश, ब्याज तथा भारत से जुड़ी रॉयल्टी या तकनीकी सेवा शुल्क। साथ ही, दोहरी कराधान से बचाव समझौतों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि एक ही आय पर भारत और विदेश—दोनों जगह कर न देना पड़े, जिससे प्रवासी भारतीयों को कर-राहत मिलती है। संकट की घड़ी में हेल्पलाइन, पासपोर्ट सेवाएं और कांसुलर सहायता यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रवासी विदेश में भी देश का संरक्षण और सहयोग पा सकें। प्रवासी भारतीय चाहते हैं कि निवेश प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी हों, दोहरी नागरिकता पर व्यापक संवाद हो, और संपत्ति, कर व उत्तराधिकार कानून स्पष्ट हों, ताकि वे दीर्घकालीन योजना बना सकें। साथ ही, वे अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कृति और भाषा के माध्यम से भारत से जुड़े रहने के पर्याप्त अवसर चाहते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों और पहचान के साथ दृढ़ता से जुड़ी रहें। ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू उच्च टैरिफ और पेशेवर भारतीयों से जुड़े वीज़ा निर्णय वहां बसे भारतीयों के लिए चिंता का विषय हैं, जिससे रोज़गार और आय पर दबाव पड़ा और भारत से आयातित वस्तुएं महंगी हुई हैं; इस संदर्भ में वे भारत सरकार से प्रभावी कूटनीतिक हस्तक्षेप की अपेक्षा रखते हैं। ज़्यादा जानें हिंदी समाचार ऐप सदस्यता ई-पेपर साक्षात्कार कौशल प्रशिक्षण युवा मनोरंजन विदेश यात्रा योजनाएँ खेल उपकरण समाचार पत्र वितरण सेवा बॉलीवुड समाचार विशेष रिपोर्ट सदस्यता प्रादेशिक समाचार प्रवासी भारतीय दिवस केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य का संकल्प है। कभी जिन्हें ब्रेन ड्रेन का प्रतीक माना गया, वही प्रवासी आज ब्रेन गेन और इनकम गेन के रूप में ज्ञान, तकनीक, निवेश और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से भारत की सामर्थ्य बन चुके हैं। उनकी उद्यमिता और नवाचार आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ करते हैं, जबकि संस्कृति, भाषा और मूल्यों का प्रसार भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक स्तर पर मजबूत करता है। भौगोलिक दूरी के बावजूद उनकी जड़ें भारत में हैं, और उनकी बौद्धिक व आर्थिक भागीदारी भारत को उभरती शक्ति से आगे बढ़ाकर वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस हमें याद दिलाता है कि जहां भी भारतीय हैं, वहां भारत जीवित है—आर्थिक सामर्थ्य, सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों के साथ।

विविध समाचार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत बन रहा बड़ी आर्थिक शक्ति : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ ०९/०३ (संवाददाता): हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिस गति से आज भारत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, उसके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्र सरकार की क्रांतिकारी आर्थिक नीतियाँ प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने "एक राष्ट्र, एक टैक्स" की अवधारणा को साकार करते हुए जी.एस.टी. लागू किया, जिससे पूरा भारत एक एकीकृत बाजार में परिवर्तित हो गया है। जी.एस.टी. सुधारों से न केवल अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है, बल्कि राज्यों के बीच व्यापार आसान हुआ है और व्यापारियों को अनावश्यक करों के जाल से मुक्ति मिली है। हाल ही में किए गए जी.एस.टी. सुधार इस बात का प्रमाण हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की "गारंटी" सदैव पूरी होती है। ये सुधार आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे।मुख्यमंत्री बुधवार को बिहार के पटना में बिहार चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए "स्वदेशी" और "मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड" के आह्वान ने देश में विनिर्माण क्षेत्र को नई दिशा दी है। हाल ही में जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत यह विजन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत यूपीआई से लेकर डीबीटी तक डिजिटल लेन–देन की क्रांति ने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। आज भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विनिर्माण और उत्पादन पर बल देकर आयात पर निर्भरता घटाई है तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरा है। केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों और सुधारों के परिणामस्वरूप आज भारत न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक सशक्त साझेदार के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में, सड़क, रेल, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के निर्माण में अभूतपूर्व निवेश हुआ है। ये सुविधाएं बेहतरीन कनेक्टिविटी, उद्योगपतियों के लिए व्यापार और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अनावश्यक कानूनों को खत्म करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, और लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें 'विकसित भारत–2047' का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमें अपने राज्यों को विकसित करना होगा। हरियाणा और बिहार को मिलकर देश की प्रगति की गति को तेज करना होगा। उन्होंने कहा कि आज यहां आकर उन्हें बिहार की मिट्टी की महक और हरियाणा की उद्यमशीलता की भावना का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यह संगम, वास्तव में, हमारे देश की प्रगति और 'विकसित भारत' के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बिहार और हरियाणा का रिश्ता केवल राज्यों की भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता प्रेम, श्रम और विश्वास का है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज बिहार में डबल इंजन की सरकार के कारण यह पूरे देश में यह प्रदेश दूसरे सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य के रूप में जाना जा रहा है। आज बिहार की जीडीपी वृद्धि दर 14 प्रतिशत से भी अधिक है। अब बिहार की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 23 प्रतिशत है, जो कृषि के हिस्से से भी अधिक है। यह सिद्ध करता है कि बिहार में उद्योगों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल माहौल बना है। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को उद्योग की जरूरतों संबंधी ट्रेनिंग के लिए भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है। यह युवाओं को उद्योग–आधारित पाठ्यक्रम प्रदान कर रही है। सरकार की 'एक जिला–एक उद्योग' योजना ने इस दिशा में क्रांति ला दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कटिहार का मखाना है, जो अब विश्व बाजार में अपनी चमक बिखेर रहा है। केंद्र सरकार ने इसे 'सुपर फूड' के रूप में स्थापित करने के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा की है, जिससे किसानों और स्थानीय उद्योगों को नई शक्ति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने के लिए बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। राज्य में निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए नीतिगत सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की गई है। सरकार ने निवेशकों को निरूशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग सहित अन्य उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए नई नीति बनाई गई है। आगामी समय में बिहार की अर्थव्यवस्था में न केवल गुणात्मक सुधार होगा बल्कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस मौके पर बिहार चौम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

हरियाणा नशे की राजधानी बन चुका है, सैनी सरकार पूरी तरह फेल : अनुराग ढांडा

चंडीगढ़ ०९/०३ (संवाददाता): आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने बुधवार को बयान जारी कर हरियाणा की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सैनी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि "हरियाणा आज नशे की राजधानी बन चुका है, और मुख्यमंत्री नायब सैनी मौन साधकर कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। अनुराग ढांडा ने कहा कि सिरसा में पिछले कुछ दिनों में 4 लोगों की नशे से मौतों ने पूरे प्रदेश का दिल दहला दिया, लेकिन सरकार और पुलिस की संवेदनाएं मर चुकी हैं। प्रदेश में नशे का यह तांडव नया नहीं है। पिछले एक साल में नाममात्र की गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि तस्कर खुलेआम नशा बेच रहे हैं। सिरसा, हिसार, कैथल, फतेहाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र जैसे जिले नशे के अड्डे बन चुके हैं। भाजपा सरकार सिर्फ ट्रांसफर की राजनीति में लगी है। उन्होंने कहा, "बेटे खो चुकी मां रो–रोकर कह रही है कि उसने नशा बेचने वालों के नाम खुद पुलिस को बताए, मगर सिरसा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री नायब सैनी, जब एक मां को न्याय नहीं मिलता, तो आपका राज किस काम का है? सिरसा में चिट्टे से लगातार मौतों के बाद ैभ्व से लेकर ैच तक को बदला जा चुका है, पर हालात जस के तस हैं। "चेहरों की अदला–बदली हो रही है, सिस्टम वही सड़ा हुआ है। अनुराग ढांडा ने बताया कि सीएम नायब सिंह ने प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई को दिखावे का खेल बना दिया है, और मौतें जारी हैं, और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। पिछले एक साल में सिर्फ नाममात्र की गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि नशे का कारोबार दिन–दहाड़े फल–फूल रहा है। नशा अब हर घर की दीवार तक पहुंच चुका है, और पुलिस प्रशासन भाजपा नेताओं के इशारे पर आंखें मूंदे बैठा है। "हरियाणा का नौजवान नशे में डूब रहा है, मांएं बेटों को खो रही हैं, और मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि हालात नियंत्रण में हैं कृ यह झूठ है, यह धोखा है! ढांडा ने कहा कि भाजपा की सरकार ने हरियाणा को "नशे का नर्क" बना दिया है। 16 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जिनमें सिरसा सबसे आगे है, जहां सात हजार से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने कहा, "नशा अब लड्डू की तरह बिक रहा है कृ खुलेआम, पुलिस की नाक के नीचे, नेताओं की छत्रछाया में। ये नाकामी नहीं, मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में पुलिस और तस्करों का गठजोड़ एक संगठित नेटवर्क में बदल चुका है। "मुख्यमंत्री नायब सिंह, आप हरियाणा के युवाओं को खो रहे हैं और फिर भी कुर्सी से चिपके हुए हैं। यह सरकार नहीं, अपराधियों की ढाल बन चुकी है, आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि तत्काल राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाए, पूरे प्रदेश में सख्त चेकिंग हो, और हर प्रभावित जिले में मुफ्त डी–एडिक्शन सेंटर खोले जाएं। साथ ही पुलिस भर्ती दोगुनी की जाए, और तस्करों के नाम सार्वजनिक कर ब्ठप् जांच कराई जाए। ढांडा ने कहा कि भाजपा और नायब सैनी का शासन हरियाणा के लिए अभिशाप बन चुका है। "हरियाणा के युवाओं की लाशें गवाही दे रही हैं कि यह सरकार नशे के कारोबार की साथी है। जनता अब चुप नहीं बैठेगी। अब आम आदमी पार्टी नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और 'ड्रग–फ्री हरियाणा' बनाकर दिखाएगी।

जालंधर में नकाबपोश लुटेरे हथियार की नोक पर ज्वेलर्स की दुकान से लाखों की नकदी और सोने के गहने लूट कर फरार

जालंधर ०९/०३ (संवाददाता): भार्गव कैंप इलाके में गुरुवार सुबह तीन नकाबपोश लुटेरे पिस्टल की नोक पर एक ज्वेलर की दुकान से लाखों की नकदी और सोने के गहने लेकर फरार हो गये। दुकान मालिक विजय के मुताबिक, उनके बेटे ने सुबह दुकान खोली थी। तभी तीन लुटेरे अंदर घुसे और आते ही पिस्टल तानकर धमकाने लगे। एक लुटेरे ने तेजधार हथियार से काउंटर का शीशा तोड़ा, जबकि दूसरे दो लुटेरे गहने और नकदी समेटने लगे।

लुटेरों ने बेटे को धमकाकर तिजोरी से नगदी निकालने को कहा। उन्होंने करीब दो मिनट में दो लाख रुपए की नकदी और गहनों से बैग भर लिया और मौके से फरार हो गये। इस दौरान लुटेरों ने दुकान मालिक के बेटे से हाथापाई भी की। घटना की सूचना मिलते ही भार्गव कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

सोनीपत में 17 दुकानों पर चला बुलडोजर

सोनीपत ०९/०३ (संवाददाता): सुभाष चौक के पास कस्टोडियन की जमीन पर बनी 17 दुकानों को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। तहसीलदार ने इन दुकानों को गिराने के लिए बुधवार को नोटिस जारी किया था। प्रशासन की तोड़फोड़ की कार्रवाई की तैयारियों को देखते हुए दुकानदारों ने वीरवार सुबह दुकानों खाली करना शुरू कर दिया था। दोपहर के समय जिला राजस्व अधिकारी सुशील शर्मा व तहसीलदार कीर्ति की देखरेख में दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। वर्ष 1977 में तत्कालीन नगरपालिका ने पार्किंग और ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित स्थान पर दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराये पर दिया था। जब इस गलती का संज्ञान लिया गया तो इसे हटाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। वर्ष 2009 में उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया, जिसके तहत 27 अक्तूबर 2009 को एक तरफ की 11 दुकानें तोड़ दी गईं थी, लेकिन एटलस रोड की ओर बनी दुकानों के दुकानदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। यह मामला कई साल तक लंबित रहा। 19 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल ने स्टे निरस्त किया था। इसके बाद 16 अगस्त 2023 को प्रशासन ने 17 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था।

22 अगस्त को दुकानदारों ने अपना सामान निकाल लिया और प्रशासन ने बिजली काटने के बाद कार्यवाही शुरू की, लेकिन दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट से फिर से स्टेटस को (यथास्थिति) ले लिया, जिससे कार्रवाई रुक गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, जहां नगर निगम ने अपने पक्ष में शपथ पत्र दायर कर स्पष्ट किया कि 2009 से इन दुकानों से किराया लेना बंद कर दिया गया था और इनका निर्माण अवैध है। तथ्यों को जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को स्टे निरस्त कर दिया और दुकानों को हटाने के आदेश दिए थे। सेक्टर–23 स्थित सामुदायिक केंद्र में 3 अक्तूबर नगर निगम की हाउस की बैठक में 225 से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा हुई। इसमें सुभाष चौक पर कस्टोडियन की जमीन पर बनी 17 दुकानों के टूटने के बाद पुनर्वास करने का प्रस्ताव पारित किया गया था।

जालंधर के 800 परिवारों को उजड़ने नहीं देंगे, लोगों के संघर्ष में हर संभव मदद करेगी कांग्रेस : परगट सिंह

चंडीगढ ०९/०३ (संवाददाता): अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और विधायक पद्मश्री परगट सिंह ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जालंधर के अंबेडकर नगर के 700–800 घरों को किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं देगी। इन सभी परिवारों को कांग्रेस की तरफ से कानूनी सहायता सहित हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से अपील की है कि वह खुद निजी तौर पर हस्ताक्षेप करके इस मामले को हल करवाएं। ताकि लोगों को न्याय मिल सके। उन्हें मौका मिलता है तो वह खुद भी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। परगट सिंह ने कहा कि निवर्तमान कांग्रेस सरकार ने पॉलिसी बनाई थी कि 12 साल से अधिक समय तक कोई व्यक्ति अगर किसी जमीन पर काबिज है तो उसे कुछ पैसे लेकर मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। इस पॉलिसी को कांग्रेस सरकार ने लागू करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इससे पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार बदल गई। मौजूदा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाया। जिसकी वजह से इस पॉलिसी का लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने कहा कि यह सिर्फ 700–800 घरों की बात नहीं बल्कि इतने परिवारों को उजाड़े जाने की बात है। ऐसा हरगीज नहीं होने दिया जाएगा। भले ही बिजली विभाग की इस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा हो, लेकिन वह करीब 70 साल से वहां बसे हुए हैं। कुछ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा लिए हैं, लेकिन अधिकतर मकानों में लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि अब आप सरकार को चाहिए कि इन लोगों को उजाड़ने की बजाए उनसे कुछ पैसे लेकर मालिकाना हक दे।

पंजाब में आप नेता को सिर में मारी गोली, पूर्व डीएसपी ने साथियों के साथ मिलकर की फायरिंग

रोपड़ ०९/०३ पंजाब के रोपड़ जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व क्ै दिलशेर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर आप नेता नितिन नंदा पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में नितिन नंदा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सिर के पीछे एक गोली लगी, जबकि दो गोलियां उनके शरीर को छूकर निकल गईं। यह घटना आनंदपुर साहिब के अगमपुर चौकदृजहाज रोड पर उस समय हुई जब नितिन नंदा एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा–तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर–उधर भागने लगे। घायल नितिन नंदा को तुरंत सिविल अस्पताल, आनंदपुर साहिब ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें च्ळप् चंडीगढ़ रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था।

स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बड़ा फैसला, वर्तमान नोडल अधिकारियों की छुट्टी, सिविल सर्जन को जिम्मेदारी

चण्डीगढ़ ०९/०३ (संवाददाता): हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन सभी में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री लगाई जाए और निर्धारित अवधि में कार्य पूरा होना चाहिए। उन्होंने वर्तमान नोडल अधिकारियों को हटा कर उनके स्थान पर सभी सिविल सर्जन को देख रेख करने का जिम्मा सौंपने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों के प्रति अपडेट रहें, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जा जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले दिनों कुछ जिलों में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान जब उन्होंने नोडल अधिकारियों से निर्माण कार्यों के बारे में पूछताछ की तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, मंगलवार 10 मार्च 2026 | पृष्ठ-6

बीजद ने डॉ. संतृप्त मिश्रा और डॉ. दत्तेश्वर होता को रास चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया

भुवनेश्वर ०९/०३ (संवाददाता): बीजू जनता दल के प्रेसिडेंट और ओडिशा असेंबली में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने शनिवार को राज्य से आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए दो कैंडिडेट अनाउंस किए। इनमें से एक को कॉमन कैंडिडेट बताया गया है, जो सभी पार्टियों से सपोर्ट मांग रहे हैं।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, पटनायक ने आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए डॉ. संतृप्त मिश्रा और डॉ. दज़ेश्वर होता को कैंडिडेट अनाउंस किया। पटनायक ने कहा, राज्यसभा चुनाव के लिए, हमारी पार्टी ने दो कैंडिडेट देने का फैसला किया है। तीसरी सीट के लिए पहले कैंडिडेट डॉ. संतृप्त मिश्रा हैं, जो हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर हैं। चौथी सीट के लिए दूसरे कैंडिडेट एक कॉमन कैंडिडेट हैं, डॉ. दज़ेश्वर होता, जो ओडिशा के जाने-माने डॉज़्टर हैं और ओडिशा हेल्थ यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर और स्ष्टक्र मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। चूंकि वह एक कॉमन कैंडिडेट हैं, इसलिए मैं सभी पार्टियों से अपील करता हूं कि उन्हें सपोर्ट करें और राज्यसभा भेजें।

जब पूछा गया कि ज़्या दोनों उज़्मीदवार जीतेंगे, तो पटनायक ने कहा, मुझे हमेशा उज़्मीद रहती है। इस बीच, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए चार जाने-माने नामों, बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी और कोयल मलिक की उज़्मीदवारी की घोषणा की। ङ्ग पर एक पोस्ट

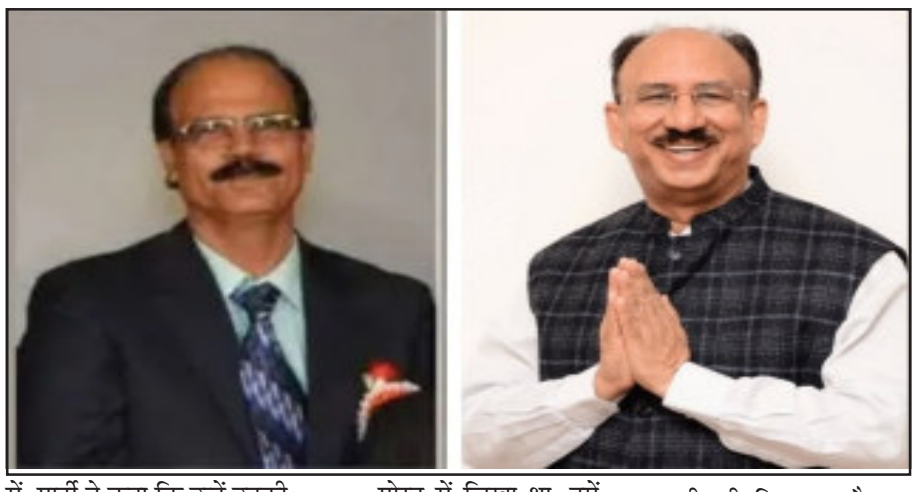

में, पार्टी ने कहा कि उन्हें उनकी उज़्मीदवारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है और उज़्मीदवारों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं दीं। पार्टी ने भरोसा जताया कि वह तृणमूल की मज़बूती की विरासत और नागरिकों के अधिकारों और सज़्मान की रक्षा के उसके वादे को बनाए रखेगी।

पोस्ट में लिखा था, हमें आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार (पूर्व DGP, पश्चिम बंगाल), मेनका गुरुस्वामी और कोयल मलिक की उज़्मीदवारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। हम उन्हें दिल से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उज़्मीद है कि वे तृणमूल की मज़बूती की विरासत और हर भारतीय के अधिकारों और सज़्मान की रक्षा के उसके पक्के वादे को बनाए रखेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, जो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, अभी पश्चिम बंगाल सरकार में इन्फॉर्मेशन टेज़्नोलॉजी और इलेज़्ट्रॉनिज़्स के कैबिनेट मंत्री हैं। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं। सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी संवैधानिक मामलों में अपने कानूनी काम के लिए जानी जाती हैं, जबकि कोएल मल्लिक बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में एक जानी-मानी हस्ती हैं।

भारतीय चुनाव आयोग (श्वष्टढ्ढ) ने बुधवार को 10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए राज्य सभा के आने वाले दो साल में होने वाले चुनावों का शेड्यूल घोषित किया, ज़्योंकि सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा होने वाला है, एक प्रेस नोट में कहा गया है।

प्रेस नोट के अनुसार, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छज़ीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल महीने में खत्म हो जाएगा, जिससे नए सदस्यों के चुने जाने के लिए सीटें खाली हो जाएंगी।

चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जिसके बाद 6 मार्च को स्ज़रूटनी होगी। कैंडिडेट 9 मार्च तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। पोलिंग 16 मार्च को होगी, और वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे होगी। चुनाव का प्रोसेस 20 मार्च तक पूरा हो जाएगा। श्वष्टढ्ढ ने निर्देश दिया है कि बैलेट पेपर पर अपनी पसंद बताने के लिए सिर्फ़ इंटीग्रेटेड वॉयलेट कलर के स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रेस नोट में लिखा है, कमीशन ने निर्देश दिया है कि बैलेट पेपर पर अपनी पसंद बताने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए पहले से तय स्पेसिफिकेशन वाले सिर्फ़ इंटीग्रेटेड वॉयलेट कलर के स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऊपर बताए गए चुनावों में अपनी पसंद बताने के लिए किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि चुनाव प्रोसेस को आसानी से और निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए ऑज़्ज़र्वर नियुक्त करके ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए।

आरएसपी में एक वर्षीय प्रशिक्षण हेतु 72 अपरेंटिस प्रशिक्षुओं का तीसरा बैच शामिल

राउरकेला ०९/०३ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) में अपरेंटिस अधिनियम, 1961/1973 के प्रावधानों के अंतर्गत 72 स्नातक, डिप्लोमा एवं आईटीआई अपरेंटिस प्रशिक्षुओं के तृतीय बैच को एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु शामिल किया गया है। प्रशिक्षुओं के लिए गोपबंधु सभागार में अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। मुज़्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन-एल एंड डी), श्री पी के साहू, ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। मंच पर महाप्रबंधक (मानव संसाधन-एल एंड डी), श्री मनोज अग्रवाल भी उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए श्री साहू ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्वरूप एवं संरचना पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा प्रतिभागियों को सक्रिय एवं सकारात्मक अधिगम दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने प्रशिक्षुओं से इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाकर अपनी तकनीकी जानकारी को सुदृढ़ करने तथा रोजगारोन्मुख कौशल विकसित करने का आह्वान किया।

दो दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को सेल एवं आरएसपी की संगठनात्मक स्वरुप से अवगत कराया गया। साथ ही कार्यस्थल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे गैस सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा तथा सामान्य स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गयी । विशेषज्ञ सत्रों एवं ऑडियो-विजुअल प्रस्तुतियों के माध्यम से कच्चे माल से तैयार उत्पाद तक की समेकित इस्पात निर्माण प्रक्रिया से परिचित कराया गया ।

कार्यक्रम के प्रारंभ में श्री अग्रवाल ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन कनिष्ठ अभियंता (मानव संसाधन-एल एंड डी), श्री आर सी राउत ने किया, जबकि तकनीशियन (मानव संसाधन-एल एंड डी), श्री डी सी गौड़ा ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

यह कार्यक्रम कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जो भारत सरकार के कौशल भारत मिशन के अनुरूप है। अपरेंटिसशिप के अवसर प्रदान कर आरएसपी का उद्देश्य युवाओं को उनके चयनित व्यवसायों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु आवश्यक ज्ञान एवं दक्षता से लैस करना है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्नातक अपरेंटिस को 12,300/- रुपये प्रतिमाह, डिप्लोमा अपरेंटिस को 10,900/- रुपये प्रतिमाह तथा आईटीआई अपरेंटिस को 10,560/- प्रतिमाह वजीफा प्रदान किया जाएगा।

९० प्रतिशत वोटरों का मिलान पूरा, ९५ प्रतिशत का लक्ष्य-ओड़िशा चुनाव आयोग

भुवनेश्वर ०९/०३ (संवाददाता): ओडिशा के मुज़्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आर एस गोपालन ने कहा कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान 2002 की मतदाता सूची से किया जा चुका है। सीईओ ने शुक्रवार को कहा कि इस मिलान प्रक्रिया के अगले 15 दिनों के भीतर पूरा होने की उज़्मीद है और कम से कम 95 प्रतिशत मिलान हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गोपालन ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एक अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने कहा, एसआईआर प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होगी। हम अब उन शेष 10 प्रतिशत मतदाताओं का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं जिनका मिलान नहीं हुआ है और हमने नागरिकों से 2002 की मतदाता सूची में उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने की अपील की है। राज्य में मतदाता सूची का अंतिम विशेष गहन

पुनरीक्षण दो दशक पहले किया गया था।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, 2002 की मतदाता सूची को आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और 2025 की मतदाता सूची के साथ मिलान किया जाएगा। उन्होंने कहा, मिलान के दौरान मतदाता का नाम, निकट संबंधी, आयु/जन्म तिथि, मतदान केंद्र, वार्ड संज्या और ईपीआईसी विवरण का मिलान किया जाएगा। बूथ स्तर के अधिकारी इस प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर सहायता करेंगे और मतदाता ईसीआईएनईटी पोर्टल, मतदाता सेवा पोर्टल, सीईओ ओडिशा की वेबसाइट और ईसीआईएनईटी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने विवरण का सत्यापन कर सकते हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे 2025 और 2002 की मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करें और बूथ स्तर के अधिकारियों को संबंधित विवरण प्रदान करें।उन्होंने कहा कि यदि नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिलता है, तो वे अपने पिता/माता का विवरण देकर इसे दर्ज करवा सकते हैं।

यदि पिता/माता का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिलता है, तो वे अपने दादा/दादी का विवरण देकर इसे दर्ज करवा सकते हैं। गोपालन ने कहा कि इस मिलान प्रक्रिया के लिए दस्तावेजों या आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है और एसआईआर शुरू होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामों का पंजीकरण किया जाएगा।

पहली ओरल पिल मिटापिवेट थैलेसीमिया मैनेजमेंट में ला सकती है क्रांति

भुवनेश्वर ०९/०३ (संवाददाता): ऐसा लगता है कि नए साल ने थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए एक बड़ी सफलता लाई है, ज़्योंकि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (स्नष्ठ) ने इस आनुवंशिक खून की बीमारी से पीड़ित वयस्कों के इलाज के लिए पहली ओरल गोली को मंजूरी दे दी है। दवा मिटापिवेट ने ज़्लड ट्रांसज़्यूजन पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण क्षमता दिखाई है। मिटापिवेट एक पाइरूवेट काइनेज एज़्टिवेटर है। चूंकि PK एंजाइम लाल रक्त कोशिकाओं में एनर्जी प्रोडज़्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मिटापिवेट को लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एनर्जी बैलेंस को बेहतर बनाने और आनुवंशिक हेमोलिटिक एनीमिया वाले मरीज़ों की मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हेमेटोलॉजिस्ट और बोन-मैरो ट्रांसप्लांट डॉज़्टरों के अनुसार, यह दवा लंबे समय तक बीमारी के मैनेजमेंट को बदल सकती है। थैलेसीमिया एक आम आनुवंशिक हीमोग्लोबिन विकार है जो अल्फा, बीटा या डेल्टा ग्लोबिन जीन में ज़्यूटेशन के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन सिंथेसिस खराब होता है और एरिथ्रोपोएसिस अप्रभावी होता है। यह पूर्वी भारत में एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है, ओडिशा ऐसे हीमोग्लोबिनोपैथी, जिसमें सिकल सेल रोग भी शामिल है, के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है।

बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और उभरती जीन थेरेपी जैसे उन्नत उपचार विकल्पों के बावजूद, मरीज़ सीमित पहुंच, ज़्यादा लागत और डोनर की अनुपलज़्धता के कारण नियमित ज़्लड ट्रांसज़्यूजन पर निर्भर रहते हैं। इंडियन कॉलेज ऑफ हेमेटोलॉजी के सचिव और ज़्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख प्रो. आरके जेना ने स्नष्ठ की मंजूरी को एक संभावित गेम-चेंजर बताया और कहा कि यह दवा मरीज़ों के नतीजों में काफी सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा, मरीज़ों में बार-बार ज़्लड ट्रांसज़्यूजन से अज़्सर आयरन ओवरलोड और लिवर, दिल और एंडोक्राइन सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान होता है।

आरएसपी के सेवानिवृज़ कर्मचारियों के जीवनसाथियों के लिए एक परामर्श कार्यशाला 'रोशनी- सक्षम साथी' आयोजित

राउरकेला ०९/०३ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र में अप्रैल-जून 2026 के बीच सेवानिवृज़ होने वाले कर्मचारियों के जीवनसाथी के लिए एक परामर्श कार्यशाला 'रोशनी- सक्षम साथी', सिविक सेंटर में आयोजित की गई । मुज़्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), श्री मानस रंजन रथ इस कार्यक्रम में मुज़्य अतिथि थे जबकि महाप्रबंधक (एसपी-2), श्री संतोष पाढ़ी सज़्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री रथ ने पति-पत्नी को सेवानिवृज़ कर्मचारियों का सहयोग करने और उनके साथ सहानुभूति रखने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे सेवानिवृज़ि के बाद की ज़िंदगी में होने वाले बदलावों को आसानी से और सकारात्मक तरीके से जी सकें। महाप्रबंधक (एसपी-2), श्री बाबूला नाहक द्वारा सेवानिवृज़ि के बाद ज़िंदगी के एक नए

दौर में आसानी से बदलाव के लिए मानसिकता पर एक सत्र आयोजित किया गया था, जबकि महाप्रबंधक (विज़ एवं लेखा), श्री राज रंजन षडंगी ने विज़ीय सुरक्षा योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया ।

उप महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री पुरुषोज़म साहू ने सेवानिवृज़ि के बाद के काम पर सुझाव साझा किए, जबकि अतिरिक्त सीएमओ (ओएचएससी), डॉ. एस कुमार ने %एक सार्थक जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के बारे में बात की। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) विषय पर उप प्रबंधक (एचआर-ईआर एंड सी), श्री एस सी नायक ने बात की। प्रारंभ में सहायक प्रबंधक (एचआर), श्री एस पी माँझी ने सभा का स्वागत किया, जबकि श्रम निरीक्षक श्री के के परिडा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया । कार्यशाला का आयोजन श्री एस सी नायक द्वारा एचआर-ईआर एंड सी टीम के सहयोग से किया गया। उल्लेखनीय है कि, कार्यशाला नियमित अंतराल पर आयोजित की जा रही है जिसमें सेवानिवृज़ होने वाले कर्मचारियों के जीवनसाथी शामिल हैं।

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के नर्सिंग कॉलेज में शामिल हों

बीएससी (नर्सिंग) पाठ्यक्रम-2026

JOIN COLLEGES OF NURSHING UNDER AFMS
BSc (NURSING) COURSE-2026

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम 2026 के लिए इच्छुक महिला उम्मीदवार का नीट (यूजी) 2026 परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है। पात्रता, नियम एवं शर्तों की जानकारी रोजगार समाचार में प्रकाशित की जायेगी। यह सूचना इस वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर भी उपलब्ध होगी।

Female candidates desirous of seeking admission to BSc(N) 2026 course at Colleges of Nursing under AFMS have to maodatorily qualify NEET (UG) 2026. The Eligibility, Terms and Conditions will be published in the Employment News in due course of time. The same will also be available onthe website.

www.joinindianarmy.nic.in

cbc 10601/11/0070/2526